अगलेगा (Agalega) द्वीपसमूह

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मॉरीशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद जगन्नाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मॉरीशस के अगालेगा द्वीप में छह सामुदायिक विकास परियोजनाओं के साथ-साथ नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जेट्टी का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया।

- इन परियोजनाओं का उद्घाटन भारत और मॉरीशस के बीच मजबूत और दशकों पुरानी विकास साझेदारी का प्रमाण है, जिससे मुख्य भूमि मॉरीशस और अगालेगा के बीच बेहतर कनेक्टिविटी की मांग पूरी होगी, समुद्री सुरक्षा मजबूत होगी और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- गौरतलब है कि वर्ष 2015 में भारत ने अगलेगा द्वीप समूह के विकास के लिये मॉरीशस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये थे। इस परियोजना में सैन्य सहयोग, एक नया हवाई अड्डा, बंदरगाह, लाजिस्टिक और संचार सुविधाएँ तथा संभावित परियोजना से संबंधित कोई अन्य सुविधाएँ शामिल है।
- अगलेगा द्वीप दक्षिण-पश्चिमी हिंद महासागर में मॉरीशस से 1,122 किमी. उत्तर में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 27 वर्ग मील (70 वर्ग किमी.) है।

गालेगा द्वीप समूह भारत के लिए सामरिक महत्व का क्यों है?

यह द्वीप समूह दक्षिण-पश्चिम हिंद महासागर में भारत की उपस्थिति को मज़बूत करेगा तथा इस क्षेत्र में अपनी शक्ति प्रदर्शन की आकांक्षाओं को सुविधाजनक बनाएगा। गौरतलब है कि भारत दक्षिण-पश्चिम हिंद महासागर में और एक खुफिया पोस्ट के रूप में हवाई तथा सतही समुद्री गश्त दोनों की सुविधा के लिये नए आधार को आवश्यक मानता है।

- यह एक "केंद्रीय भौगोलिक बिंदु" के रूप में हिंद महासागर में वाणिज्य और कनेक्टिविटी के लिये महत्त्व रखता है।
- हिंद महासागर से भारत का 95% व्यापार होता है और कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 80% समुद्र द्वारा आयात किया जाता है। इसलिये हिंद महासागर में उपस्थिति भारत के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- चीन के 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' का मुकाबला करने के लिये भारत को हिंद महासागर के बड़े क्षेत्र में उपस्थिति दर्ज करना बेहद ज़रूरी हो गया है। चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भारत के लिए रणनीतिक हितों के लिये खतरा साबित हो सकता है।
- इन परियोजनाओं से बेहतर कनेक्टिविटी की जरूरत पूरी होगी साथ ही समुद्री सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी नाव

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोच्चि में भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित और निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी का वर्चुअल तौर पर शुभारंभ किया।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- इस जहाज का निर्माण कोचीन शिपयार्ड में किया गया है। कोचीन शिपयार्ड ने भारत के पहले पूर्ण-स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल कैटामरन के डिजाइन, विकास और निर्माण की महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की।
- गौरतलब है कि समुद्री ईंधन के रूप में हरित हाइड्रोजन को अपनाना एक स्थायी भविष्य के लिए भारत की प्रतिबद्धता में सबसे आगे है, जिसका लक्ष्य

ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने के लिए 2070 तक 'शुद्ध शून्य' उत्सर्जन का लक्ष्य है।

- यह पायलट जहाज 24 मीटर का कैटामरन है जो 50 यात्रियों को ले जा सकता है। इसमें यात्रियों के लिए पूरी तरह से वातानुकूलित जगह भी है।
- कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, यह शहरी गतिशीलता को सुचारू और आसान बना देगा।
- इस पोत का प्रक्षेपण जिले में 17300 करोड़ रुपये की परियोजना की आधारशिला रखने के अवसर पर तमिलनाडु के थूथुकुडी में आयोजित एक प्रमुख कार्यक्रम का हिस्सा था।
- सीएसएल में निर्मित पोत स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को अपनाने और देश की शुद्ध शून्य प्रतिबद्धताओं के साथ संरेखित करने के लिए अग्रणी कदम को रेखांकित करता है।
- हाइड्रोजन ईंधन पोत में पूरी तरह से घरेलू तकनीक है और इसे शहरी गतिशीलता अनुप्रयोग के लिए देश के अन्य हिस्सों में दोहराया जा सकता है।

भारत सेमीकंडक्टर मिशन

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'भारत में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास' के अंतर्गत तीन सेमीकंडक्टर इकाइयां लगाने को मंजूरी प्रदान की है।
- अगले 100 दिन के भीतर तीनों इकाइयों का निर्माण शुरू हो जाएगा।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून, 2023 में गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर इकाई लगाने के लिए माइक्रोन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की थी।

स्वीकृत की गई तीन सेमीकंडक्टर इकाइयां हैं:

- 50,000 wfsm (wafer starts per month) क्षमता के साथ सेमीकंडक्टर फैब : टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ("TEPL") पावरचिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प (PSMC), ताइवान के साथ साझेदारी में एक सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करेगी। इस फैब का निर्माण गुजरात के धोलेरा में किया जाएगा। इस फैब में 91,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
- असम में सेमीकंडक्टर एटीएमपी इकाई : टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड ("टीएसएटी") असम के मोरीगांव में एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करेगी। टीएसएटी सेमीकंडक्टर फ्लिप चिप और आईएसआईपी (पैकेज में एकीकृत प्रणाली) प्रौद्योगिकियों सहित स्वदेशी उन्नत सेमीकंडक्टर पैकेजिंग प्रौद्योगिकियों का विकास कर रहा है।
- विशेष चिप्स के लिए सेमीकंडक्टर एटीएमपी इकाई: सीजी पावर, रेनेसा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, जापान और स्टार्स माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स, थाईलैंड के साथ साझेदारी में गुजरात के साणंद में एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करेगी। रेनेसा एक अग्रणी सेमीकंडक्टर कंपनी है जो विशेष चिप्स पर केंद्रित है।

इन इकाइयों का सामरिक महत्व:

- इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ने बहुत ही कम समय में चार बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। इन इकाइयों से भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम स्थापित हो जायेगा।

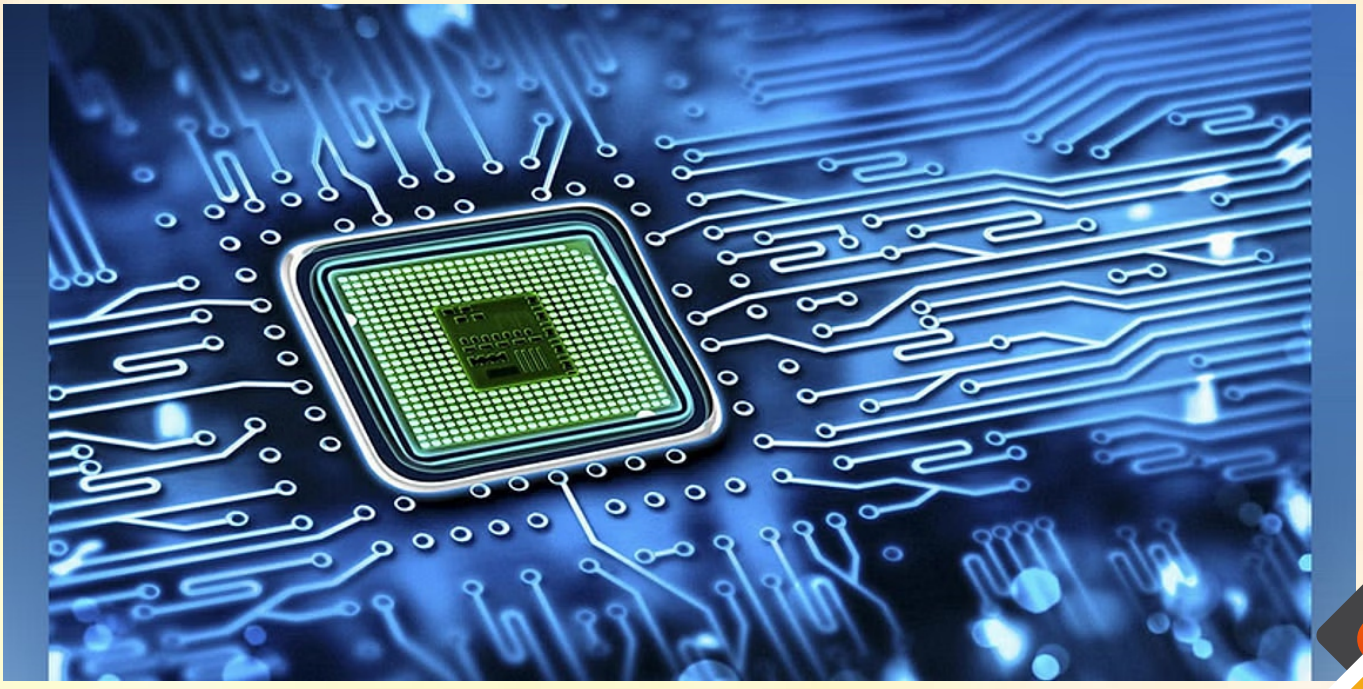

- भारत के पास पहले से ही चिप डिजाइन में गहन क्षमताएं मौजूद हैं। इन इकाइयों के साथ, हमारा देश चिप विनिर्माण (या चिप फेब्रिकेशन) में क्षमता विकसित कर लेगा।
- इसकी घोषणा के साथ ही भारत में उन्नत पैकेजिंग प्रौद्योगिकियों को स्वदेशी रूप से विकसित किया जाएगा।
- ये इकाइयां 20 हजार उन्नत प्रौद्योगिकी कार्यों में प्रत्यक्ष रोजगार और लगभग 60 हजार अप्रत्यक्ष रोजगारों का सृजन करेंगी।
- ये इकाइयां डाउनस्ट्रीम ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, दूरसंचार विनिर्माण, औद्योगिक विनिर्माण और अन्य सेमीकंडक्टर उपभोक्ता उद्योगों में रोजगार सृजन में तेजी लाएंगी।

इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में

- ISM को वर्ष 2021 में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तत्त्वावधान में कुल 76,000 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया था।
- यह देश में स्थायी अर्द्धचालक और प्रदर्शन पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिये व्यापक कार्यक्रम का हिस्सा है।
- कार्यक्रम का उद्देश्य अर्द्धचालक, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइन इकोसिस्टम में निवेश करने वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- अर्द्धचालक और डिस्प्ले उद्योग में वैश्विक विशेषज्ञों के नेतृत्व में आईएसएम योजनाओं के कुशल, सुसंगत एवं सुचारू कार्यान्वयन के लिये नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (आईबीसीए) की स्थापना को मंजूरी दे दी है।
- एलाएंस का मुख्यालय भारत में होगा और इसे 2023-24 से 2027-28 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपये की एकमुश्त बजटीय सहायता मिलेगी।

IBCA से संबंधित प्रमुख बिंदु

- यह एक प्रस्तावित मेगा-वैश्विक गठबंधन है जो सात प्रमुख बड़ी बिल्लियों : चीता, जगुआर, प्यूमा, हिम तेंदुआ , तेंदुआ, शेर और बाघ की सुरक्षा और संरक्षण की दिशा में काम करेगा।
- गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने बाघों, बड़ी बिल्ली

परिवार की अन्य प्रजातियों तथा इसकी अनेक लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण में भारत की अग्रणी भूमिका को महत्त्व देते हुए, वैश्विक बाघ दिवस, 2019 के अवसर पर अपने भाषण में एशिया में अवैध शिकार को रोकने के लिए वैश्विक नेताओं के एलाएंस का आह्वान किया था।
- उन्होंने 9 अप्रैल, 2023 को भारत के प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इसे दोहराया और औपचारिक रूप से एक इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस प्रारंभ करने की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य बड़ी बिल्लियों और उनके द्वारा फूलने-फलने वाले परिदृश्यों के भविष्य को सुरक्षित बनाना है।
- इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस की परिकल्पना 96 बिग कैट रेंज देशों, बिग कैट संरक्षण में रुचि रखने वाले गैर-रेंज देशों, संरक्षण भागीदारों तथा बिग कैट संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिक संगठनों के बहु-देशीय, बहु-एजेंसी एलायंस के रूप में की गई है।
- परिकल्पना में बड़ी बिल्लियों के कार्य में योगदान के इच्छुक व्यावसायिक समूहों और कॉर्पोरेट्स की व्यवस्था के साथ-साथ नेटवर्क स्थापित करने तथा फोकस रूप से तालमेल विकसित करने की व्यवस्था है, ताकि एक सामान्य मंच पर केंद्रीकृत भंडार लाया जा सके, इसे वित्तीय समर्थन प्राप्त हो, जिसका लाभ बड़ी बिल्ली की आबादी में गिरावट को रोकने और इस प्रवृत्ति को बदलने में संरक्षण एजेंडा को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है।
- आईबीसीए का लक्ष्य संरक्षण एजेंडे को आगे बढ़ाने में पारस्परिक लाभ के लिए देशों के बीच आपसी सहयोग करना है। आईबीसीए के पास व्यापक आधार और कई क्षेत्रों में कई गुना संबंध स्थापित करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण होगा और ज्ञान साझा करने, क्षमता निर्माण, नेटवर्किंग, वकालत, वित्त और संसाधन समर्थन, अनुसंधान और तकनीकी सहायता, शिक्षा और जागरूकता में मदद मिलेगी।
- सतत विकास और आजीविका सुरक्षा के लिए

शुभंकर के रूप में बड़ी बिल्लियों के साथ, भारत और बड़ी बिल्ली श्रेणी के देश पर्यावरणीय लचीलेपन और जलवायु परिवर्तन शमन पर बड़े प्रयासों की शुरुआत कर सकते हैं, साथ ही एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं जहां प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र फलते-फूलते रहें, और आर्थिक और विकास में केंद्रीयता हासिल कर सकें। नीतियाँ.

- आईबीसीए स्वर्ण मानक बड़ी बिल्ली संरक्षण प्रथाओं के बढ़ते प्रसार के लिए एक सहयोगी मंच के माध्यम से तालमेल की परिकल्पना करता है, तकनीकी जानकारी और धन के कोष के केंद्रीय सामान्य भंडार तक पहुंच प्रदान करता है, मौजूदा प्रजाति-विशिष्ट अंतर सरकारी प्लेटफार्मों, नेटवर्क और संरक्षण पर अंतरराष्ट्रीय पहल को मजबूत करता है। और सुरक्षा तथा हमारे पारिस्थितिक भविष्य को सुरक्षित करने और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में सहायता करता है।
- इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस समग्र और समावेशी संरक्षण परिणामों को प्राप्त करने के लिए सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ जैव विविधता नीतियों को एकीकृत करने के महत्व को पहचानता है।
- IBCA शासन में एक सभा शामिल है। गठबंधन प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करता है और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को कम करता है। बड़ी बिल्लियों और उनके आवासों की सुरक्षा करके, आईबीसीए प्राकृतिक जलवायु अनुकूलन, जल और खाद्य सुरक्षा और इन पारिस्थितिक तंत्रों पर निर्भर हजारों समुदायों की भलाई में योगदान देता है।
- आईबीसीए आपसी लाभ के लिए देशों के बीच सहयोग स्थापित करेगा और दीर्घकालिक संरक्षण एजेंडे को आगे बढ़ाने में अत्यधिक योगदान देगा। सदस्यों की संख्या, स्थायी समिति और एक सचिवालय जिसका मुख्यालय भारत में है। समझौते की रूपरेखा (क़ानून) बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) की तर्ज पर तैयार की गई है और इसे अंतर्राष्ट्रीय संचालन समिति (आईएससी) द्वारा अंतिम रूप दिया जाना है।
- आईबीसीए ने पांच वर्षों (2023-24 से 2027-28) के लिए भारत सरकार की 150 करोड़ रुपये की प्रारंभिक सहायता प्राप्त की है। कोष संवर्धन द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एजेंसियों से योगदान से होगा तथा अन्य उपयुक्त संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और दाता एजेंसियों की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के उपाय किए जाएंगे।

पीएम-सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने और एक करोड़ घरों के लिए हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने हेतु 75,021 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दे दी है।
  ध्यान रहे, प्रधानमंत्री ने 13 फरवरी, 2024 को इस योजना की शुरुआत की थी।

योजना की प्रमुख विशेषताएँ

- यह योजना 2 किलोवाट क्षमता वाली प्रणाली के लिए प्रणालीगत लागत के 60 प्रतिशत और 2 से 3 किलोवाट क्षमता वाली प्रणाली के लिए अतिरिक्त प्रणालीगत लागत के 40 प्रतिशत के बराबर सीएफए प्रदान करेगी। सीएफए को 3 किलोवाट पर सीमित किया जाएगा। मौजूदा मानक कीमतों पर, इसका आशय 1 किलोवाट क्षमता वाली प्रणाली के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट क्षमता वाली प्रणाली के लिए 60,000 रुपये और 3 किलोवाट या उससे अधिक वाली प्रणाली के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी से होगा।
- परिवार राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से सब्सिडी के लिए आवेदन करेंगे और छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए एक उपयुक्त विक्रेता का चयन करने में सक्षम होंगे। राष्ट्रीय पोर्टल उचित सिस्टम आकार, लाभ कैलकुलेटर, विक्रेता रेटिंग आदि जैसी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करके परिवारों को उनकी निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहायता करेगा।
- परिवार 3 किलोवाट तक के आवासीय आरटीएस सिस्टम की स्थापना के लिए वर्तमान में लगभग 7% के संपार्श्विक-मुक्त कम-ब्याज ऋण उत्पादों का उपयोग करने में सक्षम होंगे।

- ग्रामीण क्षेत्रों में छत पर सौर ऊर्जा अपनाने के लिए रोल मॉडल के रूप में कार्य करने के लिए देश के प्रत्येक जिले में एक मॉडल सौर गांव विकसित किया जाएगा।
- शहरी स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थान भी अपने क्षेत्रों में आरटीएस स्थापनाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन से लाभान्वित होंगे।
- यह योजना नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (आरईएससीओ) आधारित मॉडलों के लिए भुगतान सुरक्षा के लिए एक घटक के साथ-साथ आरटीएस में नवीन परियोजनाओं के लिए एक फंड प्रदान करती है।

योजना का परिणाम और प्रभाव

- इस योजना के माध्यम से, परिवार बिजली बिल बचाने के साथ-साथ डिस्कॉम को अधिशेष बिजली की बिक्री के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम होंगे। एक 3 किलोवाट प्रणाली एक घर के लिए औसतन प्रति माह 300 से अधिक यूनिट उत्पन्न करने में सक्षम होगी।
- प्रस्तावित योजना के परिणामस्वरूप आवासीय क्षेत्र में रूफटॉप सोलर के माध्यम से 30 गीगावॉट सौर क्षमता बढ़ेगी, जिससे 1000 बीयू बिजली पैदा होगी और रूफटॉप सिस्टम के 25 साल के जीवनकाल में 720 मिलियन टन CO2 समकक्ष उत्सर्जन में कमी आएगी।
- अनुमान है कि यह योजना विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, आपूर्ति श्रृंखला, बिक्री, स्थापना, ओ एंड एम और अन्य सेवाओं में लगभग 17 लाख प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा करेगी।

भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव ने नई दिल्ली में भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की।
- इस अवसर पर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) और भारतीय वन्यजीव संस्थान के सहयोग से भारत में तेंदुए की आबादी के आकलन के पांचवें चक्र का अनावरण किया गया। यह रिपोर्ट बढ़ते खतरों के बीच विभिन्न परिदृश्यों में तेंदुओं की आबादी की स्थिति और रुझान पर प्रकाश डालती है।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- भारत में तेंदुओं की आबादी 13,874 अनुमानित है, जो पिछले अनुमान की तुलना में स्थिरता दर्शाती है। हालाँकि, यह तेंदुए के निवास का केवल 70% प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें हिमालय और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों का नमूना नहीं लिया गया है।
- मध्य भारत में स्थिर या थोड़ी बढ़ती जनसंख्या प्रदर्शित हो रही है, जबकि शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदानों में गिरावट का अनुभव हो रहा है। चयनित क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग रुझानों के साथ, प्रति वर्ष 1.08% की वृद्धि दर है।
- देश में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या मध्यप्रदेश (3907) में है। इसके बाद महाराष्ट्र (1985), कर्नाटक (1,879) और तमिलनाडु (1,070) हैं। टाइगर रिजर्व या सबसे अधिक तेंदुए की आबादी वाले स्थल- आंध्रप्रदेश के श्रीशैलम में नागार्जुन सागर और इसके बाद मध्यप्रदेश में पन्ना और सतपुड़ा हैं। वर्ष 2018 में तेंदुओं की संख्या मध्यप्रदेश में 3421, महाराष्ट्र में 1690, कर्नाटक में 1783 और तमिलनाडु में 868 था।

तेंदुआ (Leopard) के बारे में

- तेंदुआ पकड़ में न आने वाला और रात्रि में विचरण करने वाला जानवर है जिसका आकार तथा रंग उसके निवास स्थान पर निर्भर करता है।
- इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा पार्डस है जो बिल्ली परिवार के सदस्य है।
- तेंदुए एशिया, उप-सहारा अफ्रीका, दक्षिणी रूस और भारतीय उप-महाद्वीप में पाए जाते हैं। भारतीय तेंदुआ (पैंथेरा पर्डस फुस्का) भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापक रूप से पाया जानेवाला एक तेंदुआ है।
- प्राकृतिक निवास स्थान का नुकसान, अवैध शिकार एवं मानव-वन्यजीव संघर्ष तेंदुओं की आबादी के लिए खतरा के रूप में चिन्हित किया गया है।
- यह IUCN की रेड लिस्ट में असुरक्षित/लुप्तप्राय प्राणी के रूप में तथा CITES के परिशिष्ट I और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची I में शामिल है।